

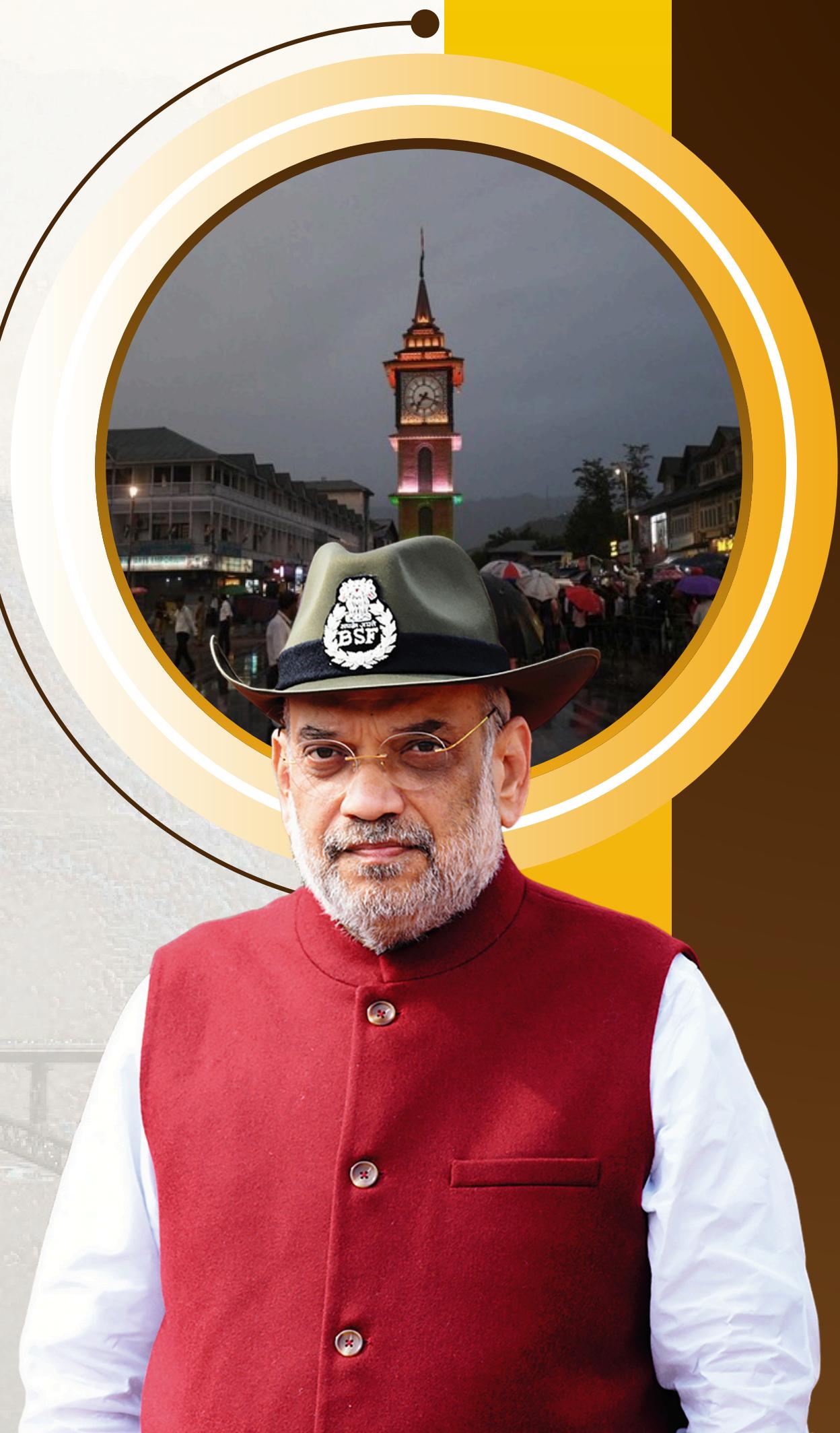
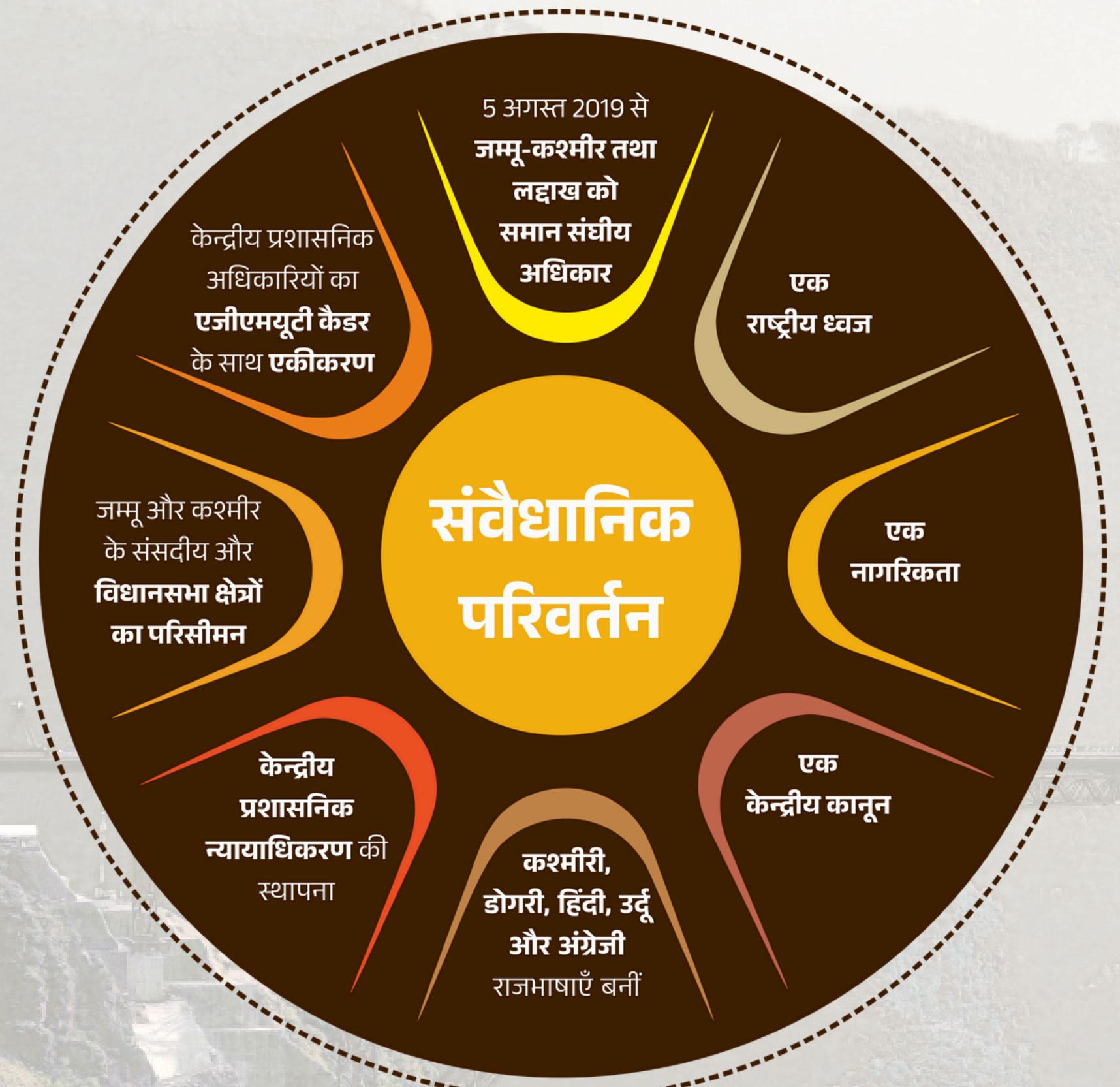
प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी जी
के नेतृत्व में

श्री अमित शाह जी
के केन्द्रीय गृह मंत्री के रूप में

6 वर्षों में लिए गये
महत्वपूर्ण निर्णय/पहलें



अनुच्छेद 370 को समाप्त करना



- मोदी 2.0 में गृह मंत्री का कार्यभार सम्भालने के 70 दिनों के भीतर 70 वर्षों की समस्या धारा 370 और 35A को समाप्त किया
- विपक्ष ने कहा खून की नदिया बह जाएँगी... **एक कंकड़ भी नहीं चला**
- 2019-25 में 2004-09 की तुलना में **हिंसक घटनाओं में 86% की कमी** आई है



- लोकतंत्र का जमीनी विस्तार: जम्मू-कश्मीर में पहली बार **ब्लॉक विकास परिषद चुनाव** में 98.3%, संसदीय आम चुनाव (2024) में 58.46%, विधानसभा चुनाव (2024), में 63% मतदान
- कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी इतिहास बन गयी



- आतंकियों के जनाजों पर प्रतिबंध लगाया गया, आतंकी समर्थकों को चुन-चुन के सरकारी नौकरियों से निकाला गया
- पहले जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोग हथियार उठाते थे, लेकिन **अब जम्मू-कश्मीर में लोकल टेररिस्ट नहीं बन रहे**
- **2 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर गए**
- **30 साल बाद सिनेमा हाल खुले, 30 साल बाद ताजिया का जलूस निकला**

- **सामाजिक न्याय:** वाल्मीकि समाज, पहाड़ियों, पद्धारी, कोली और गढ़ा ब्राह्मणों को भी आरक्षण, **EWS** को 10% आरक्षण और 15 नई **OBC** जातियों को 8% आरक्षण
- **शिक्षा और स्वस्थ्य:** जम्मू में 2 AIIMS, IIT और IIM बना, श्रीनगर में NIFT
- **फिल्म नीति, पर्यटन नीति, औद्योगिक नीति, स्टार्ट-अप नीति** द्वारा विकास के नए अवसर



शैक्षिक संस्थानों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि:

कॉलेज/सीटें	1947-2014	2014-23
मेडिकल कॉलेज BSc नर्सिंग कॉलेज	4 मेडिकल कॉलेज 13 BSc नर्सिंग कॉलेज (निजी मिला कर) 2019 तक	14 मेडिकल कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक, 1 उनानी व 1 होम्योपैथिक मिला कर 49 नर्सिंग कॉलेज (निजी मिला कर)
मेडिकल सीटें	500 MBBS सीटें 367 PG सीटें	1385 MBBS सीटें जोड़ी गईं 664 PG सीटें जोड़ी गईं 392 DNB सीटें घोषित 1690 BSc पैरा मेडिकल सीट 2990 BSc नर्सिंग सीट
डिग्री/इंजीनियरिंग कॉलेज	96 कॉलेज	55 नए इंजीनियरिंग कॉलेज सहित 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज



- **स्व-रोजगार योजना:** 7.66 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार
- **39,607 गैजेटेड, नॉन-गैजेटेड पदों पर भर्तियाँ**
- **5184 नये यूथ क्लब स्थापित किए गए, जिसमें 1 लाख से अधिक युवा सदस्य हैं**
- हौसला कार्यक्रम से **महिला उद्यमियों को मंच प्रदान कर वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है**

नक्सल मुक्त भारत



मोदी जी के नेतृत्व में श्री अमित शाह ने दशकों पुरानी समस्या “नक्सलवाद” को समाप्त करने का संकल्प लिया



भारत में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और **31 मार्च, 2026** तक पूर्णतः समाप्त हो जायेगा

- अमित शाह (केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)



हिंसक घटनाओं में
52% की कमी

2019 से 2025 तक:

1,025 मारे गये नक्सली

6,983 गिरफ्तार नक्सली

4,532 आत्मसमर्पण नक्सली

21 बड़े नक्सली लीडर्स
न्यूट्रलाइज्ड किये गए

13,634

58%

5,689

वामपंथी हिंसक घटनाएँ

मई 2004-
अप्रैल 2014

मई 2014-
अप्रैल 2024

6,536

70%

1,990

सांबंधित मौतें

मई 2004-
अप्रैल 2014

मई 2014-
अप्रैल 2024

सुरक्षा ग्रिड का विस्तार

- पिछले 6 सालों में 331 नये कैंप (नई बस्तरिया बटालियन का गठन)
- वर्ष 2025 में केवल 18 नक्सल प्रभवित जिले (2014 में 126 जिले थे)
- साथ ही, मात्र 06 नक्सल अति प्रभवित जिले (2014 में 36 जिले थे)



नक्सलियों की वित्तीय चोकिंग

- एजेंसियों द्वारा **₹93 करोड़ जब्त**



NIA में अलग वर्टीकल और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन



सिक्युरिटी रिलेटेड एक्स्पेन्डिचर (SRE)

- पिछले 10 वर्षों में **155% वृद्धि**



विकास कार्यों द्वारा नक्सल्बाद का अंत

- 12 हजार किमी सड़क निर्माण, 5731 नए डाकघर, 1007 बैंकशाखाएं, 937 ATM, 8527 (4G) टावरों, 258 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जैसी योजनाओं द्वारा सुरक्षा के साथ विकास पर फोकस
- स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, सोलर लाइट, दवाओं का वितरण, कौशल विकास, कृषि उपकरण, बीज आदि जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें मई, 2014 से अब तक ₹197.88 करोड़ के कार्य किए जा चुके हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति



टेररिज्म के खिलाफ सोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को ज़मीन पर उतरा जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटिजी और जीरो टॉलरेंस एकशन भी अपनाया

- अमित शाह (केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)



NIA के क्षेत्राधिकार में नए अपराधों का समावेश और
NIA को एकस्ट्रा-टेरिटोरीयल क्षेत्राधिकार





UAPA (एकट में संशोधन)

NIA को आतंकवादी की संपत्ति जब्त करने और एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार

- अब तक **57 व्यक्ति आतंकवादी घोषित**
- **23 संगठनों को अन-लॉ-फुल एसोसिएशन** घोषित किया
- **9 संगठनों** को प्रथम बार **अन-लॉ-फुल एसोसिएशन** घोषित



आर्म्स एकट, 1959 में संशोधन

हथियारों की अवैध तस्करी और इस्तेमाल पर रोक



राष्ट्रविरोधी इकोसिस्टम ध्वस्त किया

PFI, हुरियत व अन्य प्रतिबंधित

- **PFI नेटवर्क को ध्वस्त किया:** सितम्बर 2022 में एक ही दिन में **15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों** पर एक साथ रेड के द्वारा इस रेडिकल संगठन की कमर तोड़ी गई
- सैकड़ों PFI कैडर्स पर नकेल कसी गई तथा **PFI को देश भर में बैन किया**



आतंकवाद की फन्डिंग नियंत्रित

करने के लिए 25 सूचीय इंटेरेटेड योजना।

पूर्वोत्तर भारत में शांति और विकास



“ पहले पूर्वोत्तर में उग्रवाद, बंद, ब्लाककेड और घुसपैठ की बात होती थी लेकिन **आज विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की चर्चा होती है**”

- अमित शाह (केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)

6 वर्षों में 12 शांति समझौतों द्वारा शांति स्थापना

हिंसक घटनाओं में
71% की कमी और

10,500
से अधिक
विद्रोहियों का सरेंडर

उत्तर-पूर्व/सीमाई विवाद सुलझाना

- 2014-24 में असम-मेघालय (70% विवादित क्षेत्र सुलझाया),
- असम-अरुणाचल (700 किलोमीटर) सीमा विवादों पर समझौते



AFSPA की परिधि में कमी

- ग्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया
- असम (केवल 3 जिले), अरुणाचल प्रदेश (केवल 3 जिले और 1 अन्य जिले के 3 पुलिस स्टेशन), और नागालैंड (केवल 9 जिलों तथा 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशन) में लागू



NESAC (नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लकेशन सेंटर) की स्थापना द्वारा

- बाढ़ प्रबंधन, आर्द्रभूमि पुनर्जीवित करना, GIS आधारित मास्टर प्लान, चुनाव ई-एटलस जैसी महत्वपूर्ण पहलें



इंग्रेस के खिलाफ महाअभियान

मोदी जी के “इंग्रेस मुक्त भारत” को चरितार्थ करने के लिए इंग्रेस की

सप्लाई चेन के विरुद्ध

रुथलेस अप्रोच

डिमांड रिडक्शन के लिए

स्ट्रैटिजिक अप्रोच

हार्स रिडक्शन के लिए

ह्यूमन एप्रोच

वैश्विक स्तर पर गोल्डन ट्रांगल
और गोल्ड क्रिसेंट की जगह

डेथ ट्रांगल और डेथ क्रिसेंट नाम
प्रस्थापित किए





2019 में चार स्तरीय NCORD मेकेनिज्म और JCC का गठन



NCB द्वारा 10 कार्यालयों/स्थानों पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पूल के पहले चरण की स्थापना



आइसोलेटेड एप्रोच की जगह इंटीग्रेटेड एप्रोच

सभी राज्यों/UT में डेफीकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन

रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, पोत मंत्रालय, NCRB, NIA, भारतीय तट रक्षक बल, DRI, NMSC, ED व NTRO शामिल





इंग नेटवर्क चार्ट और मैपिंग द्वारा इग्स की पूरी सप्लाई चेन पर नकेल



'लोबल कॉऑर्डनेशन': 46 देशों के साथ इग्स के मुद्दे पर समझौते (MoU) किए गए



SIMS ई-पोर्टल, NIDAAN, N CORD पोर्टल, BISAG-N की मदद से डाटा कलेक्शन

मानस पोर्टल, और
24x7 टोल-फ्री
हेल्पलाइन

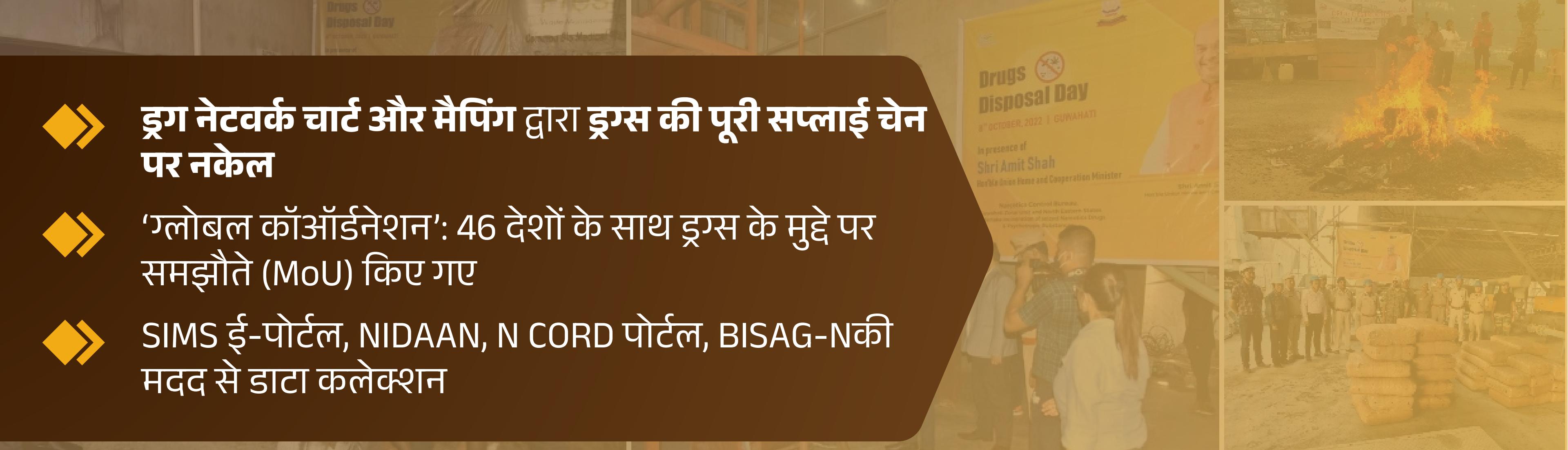
1933



गत 5 वर्षों में ₹14 हजार करोड़ का 23 हजार किलो सिंथेटिक इग्स जब्त



वर्ष 2019-24 में ₹1.1 लाख करोड़ का 73.7 लाख किलो से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया गया



नाकौं अपराधियों का डेटाबेस

नष्ट किये गये मादक पदार्थ

25.3 लाख
किलो

₹49.9
करोड़



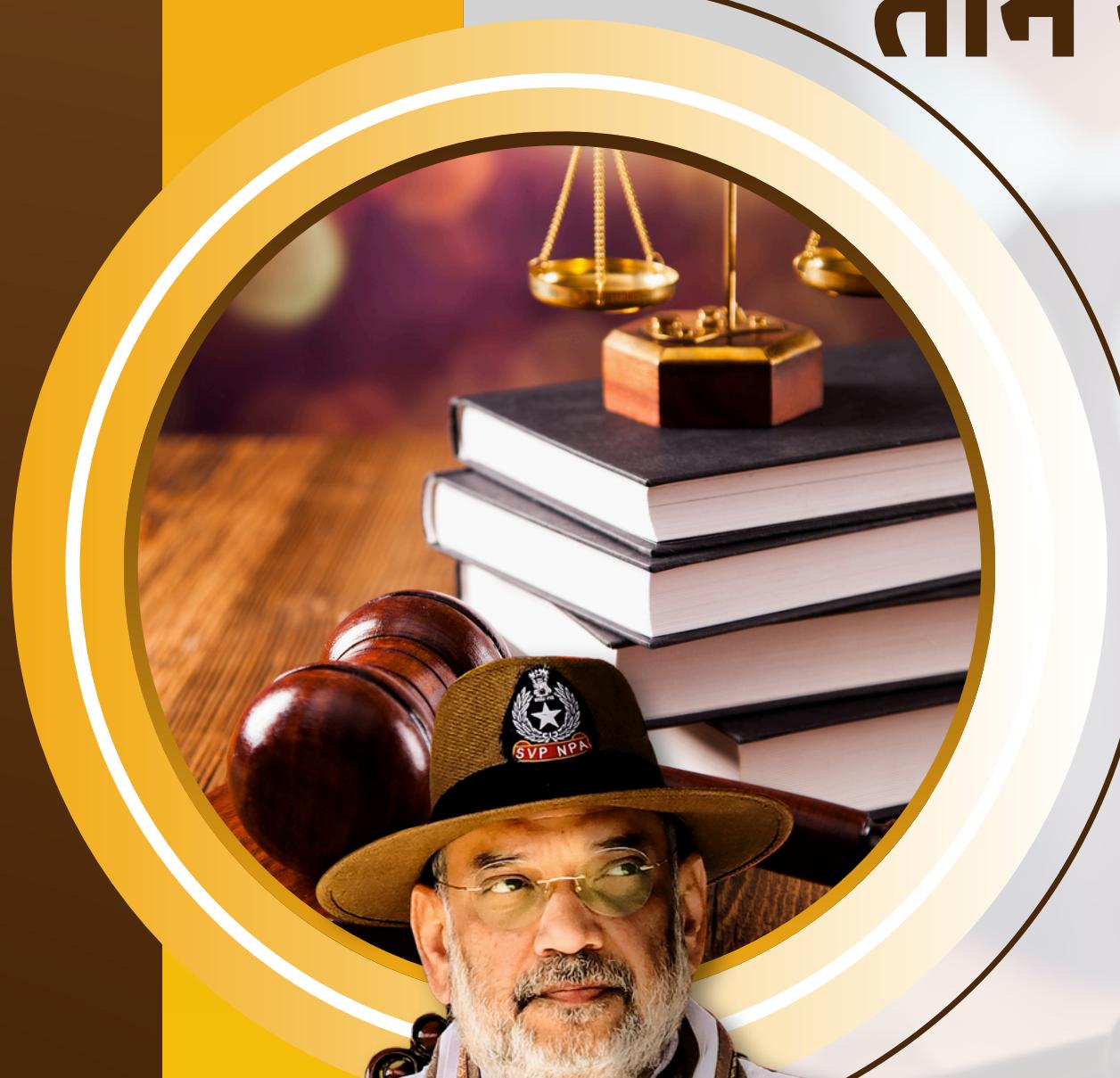
2019-24

गृह मंत्री जी के निर्देश पर NCB ने नारकोटिक्स, नाकौं-फंडिंग, नाकौं-टेरर, नशीली दवाओं की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण और अपराधियों से संबंधित विस्तृत नेशनल डेटाबेस NIDAAN तैयार किया।

यह जेलों में बंद सभी गिरफ्तार नाकौं-अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस है। इसे ICJS (इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के ई-जेल मॉड्यूल के सहयोग से विकसित किया गया है।

NIDAAN अपना डेटा ई-जेल और NCB के SIMS (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर से प्राप्त करता है।

तीन नये आपराधिक कानून (BNS, BNSS, BSA, 2023)



“
मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को
गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्त करने की दिशा में
भारतीय न्याय प्रणाली को 150 साल से पुराने
कोलोनियल कानूनों से मुक्त कर 21वीं सदी का
सबसे बड़ा रिफॉर्म लागू किया

- अमित शाह (केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री)

ICJS के 5 स्तंभों का एकीकरण

पुलिस

न्यायपालिका

कारपार

फॉरेंसिक

अभियोजन

- ◆ FIR दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक 3 वर्ष के भीतर न्याय
- ◆ महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए अलग से अध्याय (चैप्टर 5)
- ◆ आतंकवाद, और मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया। साथ ही, दंड की जगह सुधार को प्राथमिकता देते हुए पहली बार कम्युनिटी सर्विस की शुरूआत





- ◆ नागरिकों का दमन करने वाले **राजद्रोह कानून** को पूर्णतः निरस्त कर दिया
- ◆ **ई-FIR, जीरो-FIR:** भारत में कहीं भी, कभी भी FIR दर्ज करने की सुविधा
- ◆ **ट्रायल इन अब्सेंटिया** द्वारा भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी ट्रायल
- ◆ **फॉरेंसिक साक्ष्य** को अनिवार्य बनाकर और डिजिटल सबूतों को मान्यता देकर 'साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन' को बढ़ावा
- ◆ CCTNS, ई-कोर्ट, ई-प्रिजन, ई-प्रॉसिक्यूशन, ई-फॉरेंसिक, Cri-MAC द्वारा 'डेटा-आधारित' जस्टिस डिलीवरी सिस्टम

साइबर अपराध रोकथाम

साइबर सक्सेस सोसाइटी व साइबर सक्सेस भारत का
मजबूत आधार रखा

- ▶ वर्ष 2020 में 7 वर्टीकल्स के साथ I4C की स्थापना
- ▶ साइबर अपराध हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए 7 JCCT (जॉइंट साइबर क्राइम कोआडिनेशन टीम) गठित
- ▶ CCTNS से लगभग 100% पुलिस स्टेशन जुड़े | 34 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड दर्ज, जिसमें से 22 करोड़ 29 लाख अनुरोधों का पुलिस द्वारा निपटान



► जनवरी 2020 में साइबर क्राइम पोर्टल और '1930' हेल्पलाइन नंबर लांच

1930
पर प्रतिदिन करीब
60 हजार फोन कॉल आते
हैं, प्रतिदिन 5 हजार
शिकायत दर्ज

419 बैंक
और
वित्तीय मध्यस्थ जुड़े

14.47 लाख
लोगों के
₹4,725 करोड़
की वसूली

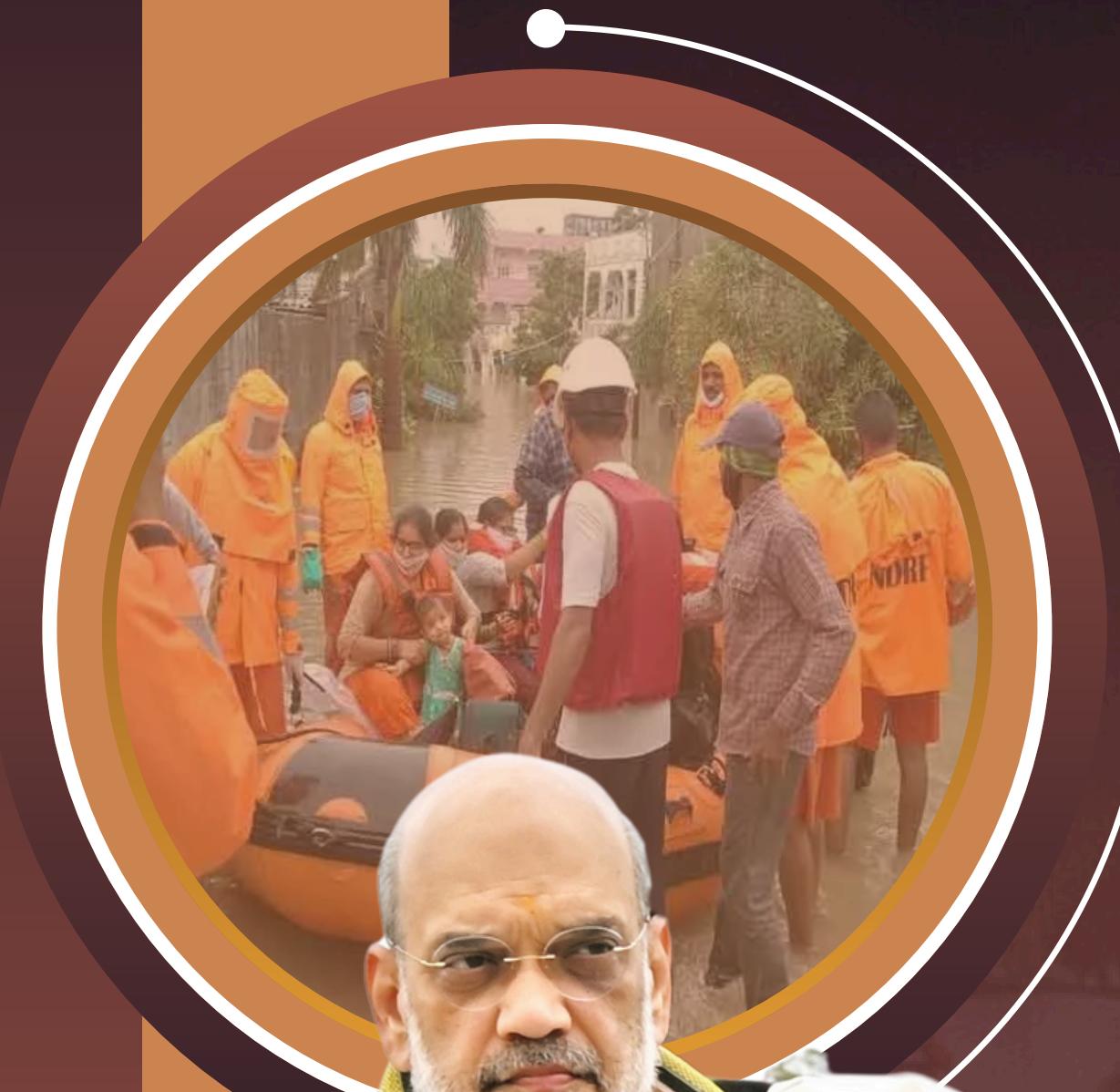


- **112 ERSS** (इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सर्विस सिस्टम) इकोसिस्टम सभी
राज्यों/UTs में चालू
- जुलाई, 2023 में "NFT, AI और मेटवर्स के युग में अपराध और सुरक्षा" पर
पहला G20 सम्मेलन

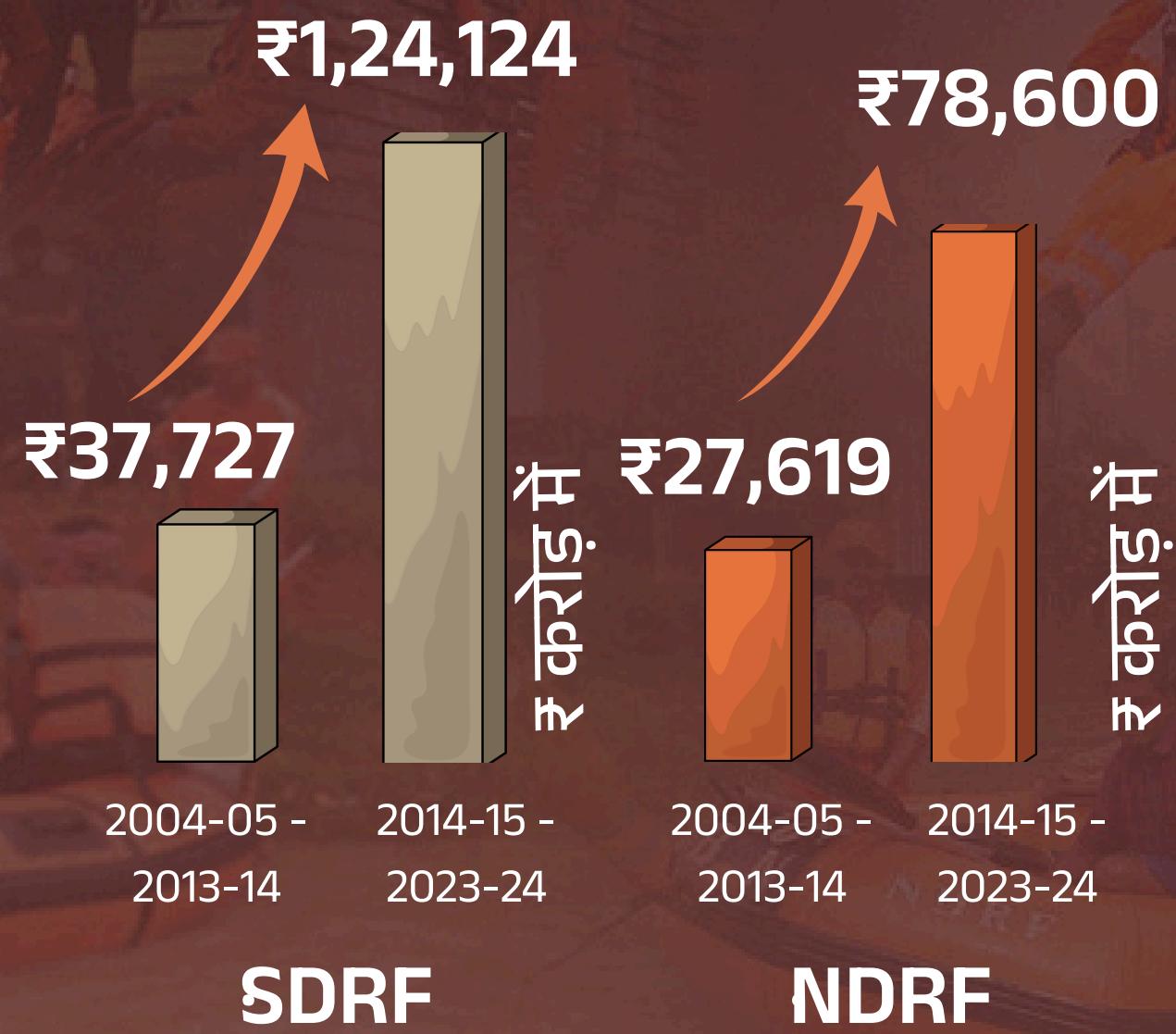


- ▶ **इंटरपोल, G7, UN, SCO, BRICS** के साथ साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम की शुरुआत।
- ▶ CCTNS (98% पुलिस स्टेशन), ई-पुलिस (100% पुलिस स्टेशन), ई-जेल (1364 जेलों), और ई-अभियोजन एप्लीकेशन (सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) में लागू
- ▶ **विदेशी साइबर ठगी कंपाउंड में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत ने बचाया**
 - ◆ कंबोडिया से **1443**, लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से **1352**, म्यांमार से **1078** और थाईलैंड से **40** नागरिकों को बचाकर स्वदेश वापस लाया है।

आपदा प्रबंधन: “जीरो कैज़ुअल्टी एप्रोच अपनाया गया”



SDRF को वित्तिरित फंड में **4 गुना** वृद्धि और
NDRF के फंड में **3 गुना** वृद्धि



► री-एक्टिव से प्रो-एक्टिव एप्रोचः

- 📌 आपदा के 10 दिनों के भीतर ही इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम (IMCT) आपदा प्रभावित क्षेत्र में भेजी जाती है
- 📌 पिछले 6 वर्षों में विभिन्न राज्यों में 97 IMCT टीम्स भेजी गयी

► अलीं वार्निंग सिस्टम में सुधारः

- 📌 7 दिन पूर्व अलीं वार्निंग मेसेज (पहले 3 से 5 दिन पूर्व भेजा जाता था)

► कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकोल (CAP):

- 📌 भौगोलिक आधारित तत्काल अलर्ट मुहैया कराने हेतु मार्च 2021 से शुरू। अब तक, 6,311 करोड़ से ज्यादा अलर्ट संदेश जारी।

► नेशनल डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड (NDMF) का गठन



वर्ष 2024-25 में ही **SDRF** के तहत ₹20,264.40 करोड़ और **NDRF** के तहत ₹5,160.70 करोड़ का फंड जारी किया गया

चक्रवातों के कारण जानमाल
के नुकसान में लगभग

98% कमी

► अंतरराष्ट्रीय पहलें:

📌 प्रधानमंत्री जी का डिजास्टर रिस्क पर **10 सूचीय एजेंडा, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI)** की स्थापना (47 देश और 8 बहुराष्ट्रीय संस्थायें शामिल)

📌 **ऑपरेशन दोस्त (तुर्की और सीरिया), ऑपरेशन सद्ग्राव (वियतनाम), ऑपरेशन करुणा (म्यांमार),** कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री जैसे महत्वपूर्ण कदम

► आपदा मित्र योजना:

📌 नागरिकों को 'विक्टिस' से - 'फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेन्स' बनाना

► आपदा प्रबंधन में तकनीकी समावेशन:

📌 मौसम, मेघदूत, फ्लड-वाच, दामिनी, मू-स्खलन, सचेत जैसे एप और पोर्टल द्वारा रियल-टाइम इनफार्मेशन शेयरिंग



नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA)

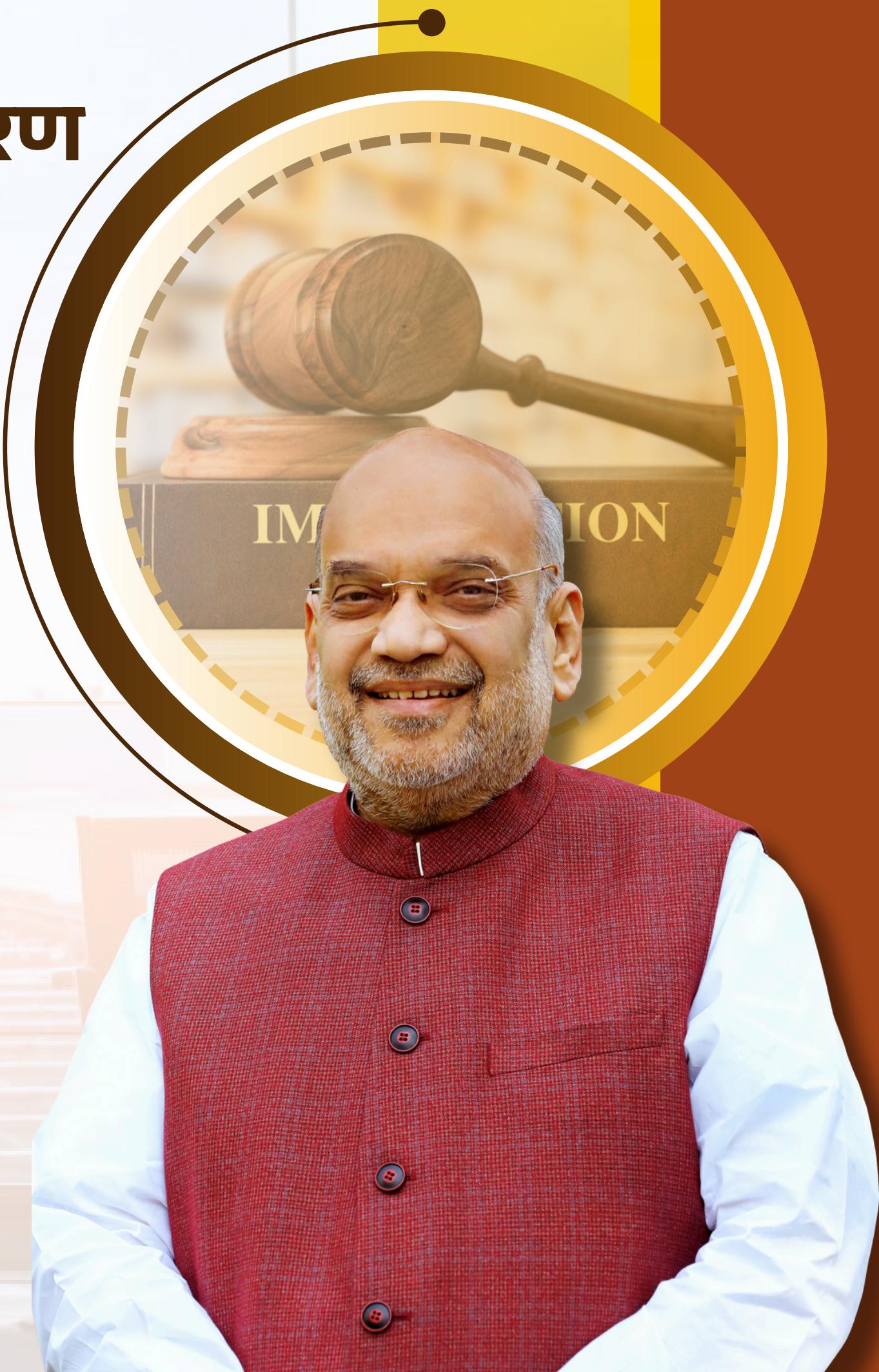


CAA केवल नागरिकता देने का कानून नहीं, बल्कि - न्याय दिलाने का कानून है

- **अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश** में धर्म उत्पीड़न के शिकार **6 धर्मों** (हिन्दू, सिख, जैन बौद्ध, इसाई, पारसी) के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान (11 मार्च, 2024 से नियम लागू)
- निवास अवधि **12 वर्ष** से **6 वर्ष** की गई। - साथ ही, **अवैध प्रवासी की परिभाषा** और सम्बंधित कार्यवाही से छूट
- आवेदन प्रक्रिया के लिए - **ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन "CAA-2019"** और टोल-फ्री नं. 1032 स्थापित

इमिग्रेशन और विदेशी कानूनों का आधुनिकीकरण

- इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक, 2025 लागू; 4 पुराने कानूनों के एक में समाहित किया - **FTI-TTP, e-FRRO** और **‘सु-स्वागतम्’** ऐप जैसी डिजिटल सुविधाएँ।
- ई-वीजा 43 से 173 देशों तक विस्तारित, वर्ष 2025 में 11.8 लाख से अधिक ई-वीजा जारी।
- विदेशी योगदान (नियमन) संशोधन नियम, 2025: - आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया गया और आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची जोड़ी गई।
- विदेशी योगदान (नियमन) संशोधन नियम, 2022: - रिश्तेदारों से प्राप्त योगदान की सूचना सीमा **₹1 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख** की गई।



अवैध प्रवासन एवं गहरी निगरानी

- कैदियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस और मिलने वालों की जानकारी के लिए **NIA का राष्ट्रीय स्तर का टेरिज्म डेटाबेस** स्थापित।
- राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS): **1 करोड़ 13 लाख रिकार्ड्स**
- इन्वेस्टीगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ओफेंसेस (ITSSO): **57.3% अनुपालन दर** (06 अप्रैल 2025)
- **निदान पोर्टल:** नशीले पदार्थों के अपराधियों के संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप सलूशन





- **विदेशी मूल के अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDOFO):**
 - विदेशी अपराधियों के संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप सलूशन
 - यह प्रणाली सभी पुलिस स्टेशनों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीयों के लिए उपलब्ध है।
- NIC की मदद से **NCRB** ने प्रिजन और CCTNS के डाटा के आधार पर **मानव तस्करों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (वर्तमान में 3.62 लाख रिकॉर्ड)** नामक वेब पोर्टल विकसित किया

फोरेंसिक सुधार



- न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 लाया गया, भारत का **पहला राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU)** बना
- फोरेंसिक शिक्षा, शोध व प्रशिक्षण का राष्ट्रीय केंद्र
- देशभर में **NFSU** के 16 केंपस प्रस्तावित, जिसमें से 7 बन चुके हैं
- **7 साल से अधिक सजा वाले केस** में फोरेंसिक अनिवार्य की गयी
- **SMFC** और **NFIES** के तहत **FSLs** (फोरेंसिक लैब्स) का आधुनिकीकरण व **NFSU, CFSL** की स्थापना।

- देश-भर में **07 CFSL** क्रियान्वित। **08 अतिरिक्त CFSL** अनुमोदित।
 - जम्मू में भी **CFSL** की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई।
 - नए कानूनों में **07 वर्ष** और उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञ का विजिट अनिवार्य किया गया।
 - देश के सभी जिलों में **मोबाईल फोरेंसिक वाहन** हेतु सहायता का प्रावधान।
 - राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को **18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट** वितरित किये गये।



पुलिस मॉडनाइजेशन

- **ICJS** (इंटरऑपरेबल जस्टिस सिस्टम), **NAFIS, NATGRID** का जिला स्तर तक विस्तार
- 'पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों/UT को सहायता (ASUMP)' योजना के तहत **2019 से 2024 तक 1,246 करोड़ रुपये राज्यों/UT को जारी किये जा चुके हैं**
- वाहनों, संचार उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और सर्विलांस टेक्नोलॉजी की खरीदी निरंतर बढ़ाई जा रही है



- देशभर के टॉप **10 थानों का मूल्यांकन** व चयन शुरू हुआ, जिससे कार्यक्षमता व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला।
- देश के **44 प्रमुख शहरों का चयन** कर 'इंडेक्स ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया' की शुरुआत— शहरी सुरक्षा में बैंचमार्क तैयार करना।
- ब्लडहाउंड जैसे भारतीय नस्ल के कुत्तों को **विस्फोटक पहचान व ट्रैकिंग** के लिए ट्रेंड किया गया; ब्रीडिंग हेतु इम्पोर्ट पर भी छूट मिली।



वृक्षारोपण

मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संवर्धन में
आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।

इसी दिशा में जनवरी 2020 में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस
बलों के सहयोग से वृक्षारोपण का प्रकल्प बनाया गया

5 वर्षों में केन्द्रीय सशस्त्र बलों द्वारा 6.1 करोड़ से अधिक
पेड़ लगाये गए

2020 - 1.47 करोड़; 2021 - 1.07 करोड़

2022 - 1.01 करोड़; 2023 - 1.54 करोड़; 2024 - 1 करोड़





इस अभियान में लगाए जाने वाले पेड़ देसी किस्मों के हैं जो स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं जैसे **नीम, इमली, पीपल, शीशम, बरगद** आदि।



पेड़ों की आयु **10 वर्ष से 100 वर्ष** की है।



वृक्षारोपण अभियान में माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री जी ने स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में जा कर भाग लिया और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया।

